

न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी—श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 16/2016

अपीलांत

रेस्पोडेंटस

चूनाराम पुत्र गंगाराम
जाति मेघवाल निवासी अरटी
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

बनाम

1. देराजराम पुत्र गंगाराम
2. तुलसाराम पुत्र गंगाराम
3. डूंगराराम पुत्र गंगाराम
4. हुकमाराम पुत्र राजूराम
5. उदाराम पुत्र हरचन्द्रराम
6. साजनराम पुत्र हरचन्द्रराम
7. गोगाराम पुत्र लिखमाराम
8. भीखी बेवा लिखमाराम
9. पोकरराम पुत्र जगमालराम
10. दानाराम पुत्र जगमालराम
जातियान मेघवाल निवासी
अरटी तहसील सेड़वा जिला
बाड़मेर
- 11 तहसीलदार चौहटन
- 12 तहसीलदार सेड़वा



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध
आदेश दिनांक 15.12.2004 द्वारा तहसीलदार चौहटन।

- उपस्थित— 1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई अधिवक्ता अपीलांत की ओर से।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 22.02.2018

1. संक्षेप में अपीलांत की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांत एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 252 रकबा 08 बिस्वा व खसरा नंबर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

253 रकबा 185.12 बीघा कुल रकबा 186 बीघा मौजा अरटी तहसील चौहटन वर्तमान तहसील सेड़वा में आई हुई है। रेस्पोंडेंटस संख्या 01 से 10 द्वारा मौके पर कब्जा काशत अनुसार व पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाड़े अनुसार खेतों का बंटवाड़ा कराने हेतु प्रस्ताव प्रशासन आपके द्वार वर्ष 2004 के तहत रखे जाने पर अपीलांत द्वारा सहमति दी गई। रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 10 द्वारा हल्का पटवारी के साथ मिलकर उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने हेतु प्रस्ताव तैयार करवाये एवं प्रस्तावों पर अपीलांत को धोखे में रखकर हस्ताक्षर करवाकर तहसीलदार चौहटन के समक्ष पेश किये। तहसीलदार चौहटन द्वारा तैयार प्रस्तावों के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2004 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांत ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांत ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन रेकॉर्ड तलब किया।
3. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलांत के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मौजा अरटी के खेत खसरा नंबर 252 रकबा 08 बिस्वा व खसरा नंबर 253 रकबा 185.12 बीघा कुल रकबा 186 बीघा भूमि पर अपीलांत एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 01 से 10 का संयुक्त रूप से कब्जा है तथा पक्षकारान अपने-अपने कब्जे अनुसार काशत करते आ रहे हैं, तथा मौके की स्थिति एवं रेकॉर्ड में भारी अन्तर है, अपीलांत का घर रेस्पोंडेंट के हिस्से में चला गया। नेखमबन्दी के दौरान पटवारी द्वारा तैयार मौका फर्द में चूनाराम की ढाणी बीच में आने से पक्की नेखमबन्दी नहीं की जा सकी। प्रशासन गांव के संग अभियान 2004 के दौरान रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 10 ने हल्का पटवारी के साथ मिलकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2004 पारित करवा गया, जो खारिज किये जाने योग्य है।
4. रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 10 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2004 के दौरान किया गया बंटवाड़ा सभी पक्षकारान की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में किया गया है, तथा बंटवाड़ा आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में



अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अमलदरामद भी हो चुका है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट चूनाराम व चारो खातेदार सगे भाई है, परन्तु अपील केवल चूनाराम द्वारा की गई है, अन्य किसी पक्षकार को कोई आपति नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से काबिल खारिज हैं।

5. रेस्पोंडेंट संख्या 11 व 12 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2004 के तहत पारित आदेश दिनांक 15.12.2004 सभी पक्षकारान की आपसी सहमति होने पर पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित किया गया है, जो विधि अनुसार सही होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाये।
6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता, रेस्पोंडेंटस संख्या 01 से 10 के अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 15.12.2004 के विरुद्ध पेश की है। अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 10 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 252 रकबा 08 बिस्वा व खसरा नंबर 253 रकबा 185.12 बीघा कुल रकबा 186 बीघा भूमि मौजा अरटी तहसील चौहटन में आई हुई है। अपीलांट एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 01 से 10 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्तानुसार किये गये विभाजन आदेश को लेकर पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त के सम्बन्ध में विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के सिद्धान्त अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकॉर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार की जाकर अपील अंदर मियाद सुमार की जाती है।



अपर कलक्टर वाड़मेर
(ए.डी.एम.)

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2004 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार सेडवा को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्धान्त एवं खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।



आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 22.02.2018 को सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)